के औसत फाइबर डायमीटर और 20 प्रतिशत के करीब मेडूलेशन और केम्प से युक्त हैं। उनमें ग्रीजी फ्लीस वेट और गुण में सुधार के लिए चयन के मापदंड तैयार किये जा रहे हैं। प्रभाग के परिचालन अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत मागरा भेड़ों के कारपेट ऊन के उत्पादन और गुण के सुधार के लिए मेढ़ों के चयन पर अध्ययन किये जा रहे हैं।

मोहेयर उत्पादन के लिए प्रजनक बकरियां : नेटिव डोज का अंगोरा बक्स के साथ संकर प्रजनन के द्वारा मोहेयर उत्पादन के लिए स्थानीय बकरियों में सुधार लाने का प्रयास किया गया है और परिणाम से पता चला है कि 3/4 अंगोरा और हाइयर क्रासेज मोहेयर उत्पन्न कर सकती है।

शुष्क जलवायु में भेड़ उत्पादन के लिए अनुकूलतम प्रजनक मौसम : इस प्रभाग में गर्म शुष्क जलवायु के अन्तर्गत भेड़ों के प्रजनन के अनुकूलतम मौसम पर एक तदर्थ योजना चलाई गई। इसके अन्तर्गत भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त पोषण के स्तर का ओएस्ट्स के प्रकोप पर प्रभाव नहीं पड़ा—इससे पता चलता है कि उष्ण-कटिबन्धीय क्षेत्रों की भेड़ पूरे वर्ष प्रजनन करती हैं। फिर भी भेड़ की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए जिसमें ग्रीजी ऊन का उत्पादन और दूध छुड़ाये गये मेमने का वजन शामिल है, मार्च-अप्रैल और अगस्त-सितम्बर का मौसम सबसे अच्छा पाया गया।

गर्भाधान के शुरू में भेड़ों का इलाज : भेड़ों में शुरू के गर्भाधान का पता लगाने के लिए एक इम्यूनोलौजिकल टेस्ट "रोंसेट्टी इनहिबिटिसन टेस्ट" का मानकीकरण किया गया है।

ग्रामीण बाजारों के विकास का प्रावधान

3185. **श्री बापूसाहिब परूलेकर :**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 1983 के अनुसार इस योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मार्च, 1983 के अंत तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में चुने हुए नियमित बाजारों, प्राथमिक ग्रामीण बाजारों तथा थोक बाजारों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) छठी योजना के दौरान 31 मार्च 1983 तक पिछड़े क्षेत्रों में 1311 प्राथमिक ग्रामीण बाजारों और 47 थोक बाजारों के लिए 15.72 करोड़ रुपये तथा 171 चुने हुए नियमित बाजारों के लिए 6.14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता बंटित की गई है।

वन अनुसंधान संस्थानों और वन अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल

3186. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की वन अनुसंधान संस्थाएं और वन अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं तथा ऐसी संस्थाओं और केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने वन अनुसंधान और प्रशिक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित वन प्रबन्ध संस्थान की वर्तमान गतिविधियां और काम काज क्या है तथा इस संस्थान की विस्तार सम्बन्धी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संस्थान की उपयोगिता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन केवल एक वन अनुसंधान संस्थान है, जो उत्तर प्रदेश में देहरादून में स्थित है। विभिन्न स्तरों के वन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के 9 वन महाविद्यालय हैं, जो देहरादून (उत्तर प्रदेश), बालाघाट (मध्य प्रदेश), कोयम्बतूर (तमिलनाडु), कुर्स्यांग (पश्चिम बंगाल), चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) तथा बर्नीहाट (असम) में स्थित हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है :—

	(लाख रुपए)
1980-81	3,34.83
1981-82	3,95.95
1982-83	6,09.31

(ग) संस्थान के प्रथम निदेशक की अगस्त, 1983 में अचानक मृत्यु हो गई और दूसरे निदेशक की नियुक्ति होने तथा संकाय के पदों से भरे जाने तक इस समय संस्थान अपने सामान्य कार्यों तथा कार्यकलापों को करने में असमर्थ है। संस्थान के विस्तार संबंधी योजना के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) निदेशक की नियुक्ति करने तथा संकाय के सदस्यों के पदों को भरने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है।

Release of F.C.I's Fertilisers

3187. SHRI G. BHOOPATHY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount of fertiliser released by Fertiliser Corporation of India for sale on reduced prices from the old stocks and how much was actually sold so far in different States ;

(b) the quantum of F.C.I.'s fertiliser allocated to Andhra Pradesh during 1983 Kharif season under different categories ; and

(c) safeguards taken to ensure quality of F.C.I.'s fertiliser ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The Department of Agriculture and Cooperation launched a 'Special Rebate Scheme' for liquidation of imported Urea and Di-amonium phosphate lying with the Food Corporation of India for more than two years on the date of sale at a rebate of 10% of the notified consumer prices to the farmers. Sale of these fertilisers are being made through major manufacturers having well established sales network, through pool handling agencies and if necessary through Institutional Agencies. The State-wise quantities lifted out of Special Rebate Scheme stocks and quantities sold upto 30-11-1983 separately for Urea and Di-ammonium Phosphate, by the Fertiliser Corporation of India are as under :